Dr. Vinod Baitha
Deptt of Economics
Marwari college
Darbhanga

Economics D.II Hons Lecture - N. 11

व्यापार चक्र का नियंत्रण control Trade cycle

व्यापार चक्र में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद तेजी और तेजी के बाद मंदी बारी-बारी से आती रहती है यह सामाजिक हितों के लिए घातक होता है और अर्थव्यवस्था में भारी संकट उत्पन्न कर देती है अतः व्यापार चक्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता है व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख उपाय निम्न लिखित है।

1. प्रशुल्क अथवा राजकोषीय नीति।
2. मौद्रिक नीति।
3. भौतिक नियंत्रण।
4. अन्य उपाय।

1. प्रशुल्क नीति अथवा राजकोषीय नीति — आर्थर स्मिथीज के अनुसार "प्रशुल्क नीति वह है जिसको सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है" प्रशुल्क नीति के अन्तर्गत निम्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है।

A. व्यय में परिवर्तन — आय, उपभोग और विनियोग पर किये गए व्यय के योग के बराबर होती है अतः अपस्फीति की रोक थाम के लिए उपयुक्त नीति सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है तथा स्फीति को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। चूँकि सार्वजनिक व्यय कुल व्यय का एक अंश है, इसलिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से कुल व्यय बढ़ता है और सार्वजनिक व्यय घटने से कुल व्यय घटता है।

यदि किसी अर्थव्यवस्था में अपस्फीतिजनक (मंदी) परिस्थितियाँ विद्यमान तो प्रश्न उठता है कि सरकार व्यय की किन मदों में व्यय बढ़ावे। मोटे तौर से सरकार को निम्नलिखित तीन प्रकार के व्ययों को बढ़ाना चाहिए।

i. उपभोग को प्रभावित करने वाले व्यय — सरकार को वृद्धावस्था, बेकारी अपाहिज की सहायता इत्यादि के रूप में आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ताकि वे व्यक्ति जिनकी आय कम है उनकी उपभोग शक्ति बढ़े। हेलर के अनुसार 1933-39 की अवधि में इस प्रकार की सहायता का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया।

ii. व्यक्तिगत विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व — सरकार को उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए। और व्यक्तिगत क्षेत्र की स्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े। और कार्यशील बन सके

iii. सार्वजनिक व्यय — सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे सड़कों, भवनों, पार्कों, स्कूलों, नहरों, अस्पतालों, बन्दरगाहों आदि के निर्माण में व्यय करना चाहिए। इस प्रकार के सरकारी व्यय से प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फीति काल में स्वयं समाप्त किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

B. करों में परिवर्तन — करों में परिवर्तन निजी व्यय को प्रभावित कर के राष्ट्रीय आय तथा रोजगार को प्रभावित करते है। मंदी काल में कर नीति ऐसी होनी चाहिए। जिससे की उपभोक्ता और विनियोग व्यय को प्रोत्साहन मिले। वस्तुओं पर लगाए गए करों को बराबर इतना कम कर दिया जाना चाहिए कि जनता के उपभोग व्यय में वृद्धि हो सके। उत्पादन कर, बिक्री कर आदि करों में कमी करने से एक ओर तो व्यक्तियों के उपभोग व्यय बढ़ेगें तो दूसरी ओर उत्पादकों तथा विक्रेताओं की आय बढ़ जाएगी। और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होगें। फलतः आय रोजगार और विनियोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार व्यवसायिक और विनियम करों में वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

दूसरी ओर स्फीति काल में क्रय शक्ति को घटाने के लिए उपर्युक्त करों की दरों में वृद्धि करनी चाहिए। तथा नए करों को लगाना चाहिए।

C. सार्वजनिक ऋण — सार्वजनिक ऋण का उपयोग भी मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति को दूर करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत सरकार जनता से उधार लेती है और उसका जो भुगतान करती है दोनों सम्मिलित है। जब सरकार जनता से उधार लेती है। तो उसका प्रभाव कर रोपण के समान होता है क्योंकि इसके द्वारा जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति सरकार के पास उधार के रूप में आ जाती है। इस प्रकार जब सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान करती है तो उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय के समान पड़ता है क्योंकि इससे व्यक्तियों के पास मूल धन और ब्याज के रूप में अतिरिक्त क्रय शक्ति आ जाती है। और प्रभाव पूर्ण माँग में वृद्धि होती है।

राजकोषीय नीति की सीमाएँ। यद्यपि विभिन्न राजकोषीय यंत्रों के समुचित प्रयोग से हम आर्थिक स्थायित्व की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं परन्तु राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं।

i. सार्वजनिक व्यय में आए दिन सहसा प्रयोग करना आसान नहीं है।
ii. सरकारी योजना भी जल्दी-जल्दी बदली नहीं जा सकती है।
iii. कर प्रणाली में आए दिन आकस्मिक परिवर्तन करना आसान नहीं है।
iv. राजकोषीय नीति दुधारी तलवार की भाँति है। यदि थोड़ी सी भी सरकारी व्यय की दिशा में गलती हुई तो या तो स्फीति हो जाएगी या मंदी आ जाएगी।

2. मौद्रिक नीति — मौद्रिक नीति से आशय आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन है मौद्रिक नीति के अन्तर्गत वे सभी उपाय आ जाते हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के उपकरणों को अधिक प्रभावशाली बनाता है मौद्रिक नीति मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति को रोकने में सहायक होती है। केन्द्रीय बैंक जिन तरीकों से साख का नियंत्रण करता है उन्हें साख नियंत्रण के उपकरण कहते हैं।

A. बैंक दर नीति — बैंक दर ब्याज की वह दर है जिसपर केन्द्रीय बैंक अन्य सदस्य बैंकों को उधार देता है। यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है तब व्यापारिक बैंक भी अपने ऋणों के ब्याज दरों में वृद्धि करने के लिए विवश होते हैं। इसके विपरीत यदि बैंक दर कम कर दी जाए तब व्यापारिक बैंक भी अपने ऋणों की ब्याज दरों को कम करने में भी समर्थ हो जाते हैं।

Scanned by CamScanner

स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक दर में वृद्धि कर देनी चाहिए। बैंक दर में वृद्धि हो जाने के कारण व्यवसायिक तथा उपभोक्ता लोगों से अधिक ऋण लेना पसंद नहीं करते जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबावों की तीव्रता में गिरावट आ जाती है।

इसके विपरित अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए केन्द्रीय बैंक को बैंक दर घटा देना चाहिए। ताकि ऋण सस्ता हो जाय और ऋणों पर आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले।

B. खुले बाजार की क्रियाएं — स्फीति को रोकने के लिए उपयुक्त नीति यह है कि केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचें। प्रतिभूतियों के विक्रय के फलस्वरूप व्यवसायिक बैंक की जमा में कमी आ जाती है। क्योंकि क्रेता अधिकतर प्रतिभूतियों का भुगतान बैंक जमा में से करते हैं। व्यापारिक बैंकों की जमा में कमी होने से उनकी उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। और बैंक ऋण घट जाते हैं। जिससे स्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ कम हो जाती हैं इसके विपरित मंदी काल में केन्द्रीय बैंक को प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए। ताकि व्यापारिक बैंकों के यहां नगद जमा की मात्रा बढ़ जाए और उनकी उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो तथा साख विस्तार हो और यह बात मंदी काल में भी वांछित है।

C. प्रासंगिक अनुपातों में परिवर्तन — जब देश में मुद्रा प्रसार हो तो केन्द्रीय बैंक को प्रासंगिक अनुपात को बढ़ा देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों द्वारा रखा जाने वाला अनुपात 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाता है। तो व्यापारिक बैंकों को केन्द्रीय बैंकों के पास अधिक धनराशि जमा करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी अनुपात में व्यापारिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण दे सकने की शक्ति सीमित हो जाएगी। फलतः मुद्रा प्रसार की तीव्रता कम हो जाएगी। इसके विपरित मंदी काल में प्रासंगिक अनुपातों को घटा देना चाहिए।

D. मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन — मार्जिन की ऊंची दर मौद्रिक प्रसार को रोकने में समर्थ होती है। उदाहरण के लिए मान लिजिए व्यापारिक बैंक गेहूं के स्टॉक की जमानत पर स्टॉक के वर्तमान मूल्य के 70% अंश उधार देता है इसका अर्थ यह है कि मार्जिन 30% है अब मान लिजीए केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आदेश देता है कि वे मार्जिन 30% के स्थान पर 50% कर दें ऐसी दशा में व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक को प्रतिभूतियों के मूल्य के 50% से अधिक ऋण नहीं दे सकते। अर्थात 100 रुपये के गेहुँ के स्टॉक पर 50 रुपया ही ऋण दिया जा सकेगा। फलतः बैंक ऋण घट जाएगी। अतः केन्द्रीय बैंक की नीति यह है कि तेजी के काल में मार्जिन की आवश्यकता को बढ़ा दे। और मंदी काल में मार्जिन की आवश्यकता घटा दे।

E. उपभोक्ता का साख नियमन — स्फीति काल में केन्द्रीय बैंक को उपभोक्ता साख संकुचन के लिए अधिकांश उपभोग वस्तुओं पर उपभोक्ता साख नियंत्रण नियमन लागू करना चाहिए, विशिष्ट वस्तुओं की पहली किश्त की राशि अधिक रखनी चाहिए तथा भुगतान काल की अवधि को कम कर देना चाहिए। मंदी काल में उपभोक्ता साख विस्तार के लिए ...

छूका कर देना चाहिए।

मौद्रिक नीति की सीमाएँ – इन मौद्रिक नीति के उपायों की सीमा होती है।

1. अकेले मौद्रिक उपचार की मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन पर रोक लगाने हेतु सफल प्रमाणित नहीं हुए हैं। सन् 1929-33 में अमेरिका में कठोर साख नीति का पालन करने पर भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही थी।

ii. वास्तविक विनियोगकर्त्ताओं पर अंकुश रखने पर सरकारें असमर्थ रहती हैं।

iii. मौद्रिक नीति प्राय: इतनी कोमलता से लागू की जाती है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर होती।

प्रो० हॉम का कहना है कि "अकेली मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता नहीं ला सकती। इसी प्रकार रेडक्लिफ का विचार है कि "स्फीति काल में मौद्रिक नीति प्रभावशाली हो सकती है परन्तु मंदी काल में इसकी क्षमता अत्यन्त सीमित है।

3. भौतिक नियंत्रण

कीमत नियंत्रण, कीमत स्पोर्ट तथा राशनिंग, प्रो० फिशर ने कीमत नियंत्रण को स्फीति प्रभु बना करने के लिए एक उत्तम साधन माना है। कीमत नियंत्रण के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है जिससे अधिकतम कीमतें स्फीति काल में नहीं बढ़ सकती। इसके विपरीत कीमत स्पोर्ट के अन्तर्गत कम से कम सीमा निर्धारित की जाती है जिससे कीमतें मंदी में नहीं गिरती। ज्यों ही कीमतें इन सीमाओं को पार करती हैं, सरकार स्फीति काल में कीमत नियंत्रण के साथ-साथ राशनिंग व्यवस्था लागू कर के अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। इसके विपरीत मंदी काल में ज्यों ही कीमतें गिरती हैं सरकार खुले बाजार में भारी स्टॉक खरीद कर उत्पादकों की रक्षा करती है। इन नीतियों की सफलता के लिए भारी साधन, उचित समय व कुशल प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है।

4. अन्य उपाय – अन्य उपाय को दो भागों में बाँटा जाता है Ⓐ आयात-निर्यात Ⓑ आयात-निर्यात – व्यापार-चक्र को आयात-निर्यात की मात्रा को नियंत्रित कर भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि देश में आर्थिक तेजी अर्थात् मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में निर्यातों को प्रतिबंधित तथा आयातों को छूट देना चाहिए। ताकि देश में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर उसकी कीमत स्तर में कमी की जा सके। इसी प्रकार तेजी काल में विदेशी पूँजी को भी आयात किया जाना चाहिए। इसके विपरीत आर्थिक मंदी काल में निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ताकि वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर कीमत नियंत्रित किया जा सके। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं परस्पर व्यापार विनियोग टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान तथा पूँजी के आवागमन के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं को उत्तरोत्तर अधिक उन्नति के अवसर मिलते हैं इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव में कमी आती है।

B बाजार में व्याप्त कालाबाजारी, चोर बाजारी, सट्टा प्रवृत्ति आदि को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही जनसंख्या वृद्धि की दर को भी नियंत्रित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार हेतु प्रभावी नीति बनाना चाहिए।

इस प्रकार राजकोषीय, मौद्रिक तथा अन्य मौलिक माध्यम से व्यापार चक्र नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का आना स्वाभाविक है लेकिन उचित समय पर उपयुक्त आर्थिक नीति को अपना कर इसपर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी होता है ताकि आर्थिक ...